



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—खण्ड-II  
PART II—Section 3—Sub-Section (II)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1992/ज्येष्ठ 4, 1914

No. 311]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1992/JYAISTHA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जाती हैं किससे इक यह अलग संकालन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रस्तावना-कार बोर्ड

### प्रधिकूलता

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

ग्राह्य-कर

का. ना. 357 (प्र).—केन्द्रीय प्रस्तावना-कार बोर्ड ग्राह्य-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राह्य-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, प्रथमतः—

1. (1) इन नियमों का संभिप्त नाम ग्राह्य-कर (दसवा संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये 1 मर्च, 1991 से लागू समझे जाएंगे।

2. ग्राह्य-कर नियम, 1962 में, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम ग्रन्ति स्थापित किया जाएगा, प्रथमतः—

“6क. धारा 43प के उपर्युक्त प्रत्येक लोक वित्तीय संस्था, मन्त्रालय बैंक, राज्य वित्तीय निगम और राज्य लोकोगिक वित्तियालय निगम की दशा

में, वहाँ लागू होंगे जहाँ व्याज के रूप में उठकी आय, उड़ंत और गंकालपद व्यापारों के निम्नलिखित प्रबंधों के संबंध में है, प्रथमतः—

(क) (i) ग्राह्य या अटके द्वारा जहाँ उपर्युक्त (ii) में विनियिष्ट प्रकृति की आनियमिताओं, उधार लेने वार्ताओं के लेखाओं में छह मास और उससे अधिक की अवधि के लिए व्यापार में ग्राही है और जहाँ लेखाओं के विनियमन की न्यूनतम संभावनाएं महीं हैं या जहाँ लेखाओं व्यवसा ऐसे लेखाओं की बाबत निम्न प्रकार की कारणता के अधिकारिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जैसे —

1. व्यापार का नग्न ग्राहक के परिणामस्वरूप कारबाह में आभासी असरोद्ध;

2. ग्राह्यालय के लिए लगाकार अनुरोध करना या लेखा में नियमों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जैक जाती करना;

3. काय किए गए विल या भित्तिकारे के भूगतान तीन मास और उससे अधिक के लिए अतिशोष्य रहते हैं या ऐसे विलों की वस्त्री में उधार लेने वाले कठिनाइया उपचार करता हैं;

4. ऐसे सावधि व्यापारों, किसी की दशा में जो छह मास या उससे अधिक की अवधि से अतिशोष्य हैं;

5. देंक द्वारा अपेक्षित ईमासिक या आर्थिक प्रवालन विवरण या स्टाक विवरण अथवा तुलनपत्र और अस्य जानकारी देने में उदाहरणों वाले द्वारा अस्पष्ट विस्म्ब;

6. निरीक्षण के बीचन मध्यस्थिति स्टाक का धीमा संबलन या अवरोध;

7. कारबार के निरीक्षण या नियमन अथवा बंद करने के बीचन अश्लोकित क्रियाकलापों का इम या नमन्य स्तर;

8. मूल्य आवश्यकताओं जैसे दस्तावजों का निष्पादन, जब अपेक्षित (i), अंतिरिक्त प्रतिभूति वेसे का अनुपालन करने में स्थगातार विस्म्ब या ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करना;

9. महयोगी एकरों को निधियों का प्रयोजन या कारबार से प्राप्त पूँजी आवश्यियों का अर्जन अथवा धार लेने वाले द्वारा अकिञ्चित रूप से बड़ी रकम निकाला जाना;

10. परियोजना के कार्यक्रम से आशयित अनासंजन जिसके कारण नागर में भारवान बढ़ि होती है और अतिरिक्त मालाधिक वित्त की आवेदा होती है;

11. समापन पर दबाव जिसके कारण कर्मकारी की मजदूरी या कानूनी जोधों अथवा कार्यालय और कारबार के परिवर के किये का संदाय न करना;

12. चालू आविष्यों से अधिक चालू दायित्व;

13. उधार लेने वालों के लेन्ड्रिं परोक्षकों द्वारा अवलोकित कोई भारी अनियमितता जिसका मुद्दार किया जाना चाही है;

14. एक के दिनीय विवरणों द्वारा प्रकटित प्रायमिक कमजोरी उदाहरणार्थ एक साल के बाद स्थगातार रोकड़ हानि।

(ii) उधार लेने वालों के लेन्ड्रिं में उपर्यंत (i) में निर्दिष्ट अनियमितताएं निम्नलिखित हैं, --

1. जहां लेक्षाओं से, अस्यादी अवधि के लिये प्राहरण शक्ति, भंजूर की गई सीमा, स अधिक अध्यादान;

2. साथाधि हानि की बाबत किसी लाह मास से अध्यून के लिये अविश्वाय है या प्रत्ययत्व के प्रधीन प्रायात विलों अथवा आपरागित संभाय के अर्धान किसी तीन मास से अध्यून के लिये अविश्वाय रक्ती है;

3. क्य किये गये विलों में कुल बकाया का 10% से 15% से अधिक विल या उधार लेने वाले के मिलिकाटे लेन्ड्रिं तीन मास से अध्यून अवधि के लिये संभाय के लिये अविश्वाय हैं और असंदर्भ विलों के मंदिर में प्रतिक्षय तुरन्त नहीं हो रहा है।

(अ) वापस लिये गये प्रधिम, अर्थात् जहां प्रतिवाद अतिशंकास्पद हो और एक को पुनःप्रबन्धित करना उचित नहीं समझा जाता हो और प्रधिमों को वापस लेने के लिये निर्णय ले लिया गया हो।

(ग) बाद फाइल किये गये लेन्ड्रिं अर्थात् जहां विधिक कारंवाद या बसूली कार्यवाहिया प्राप्त कर दी गई है और प्रधिम की बसूली के लिये बाद सम्भित है।

(घ) छिकीगत क्षण, अर्थात् जहां बाद फाइल कर दिये गये हैं और छिकी प्राप्त कर दी गई है तथा ऐसी छिकी निष्पादन के लिये सम्भित है।

(इ) उनके क्षणों की बसूली, प्रतिभूति, की कीमत में हुई कमी, प्रतिभूतियों को प्रवक्ष करने और नियमित करने में कठिनाई, या उधार लेने वालों की बैंक की शोध रकमों को भागतः या पूर्णतः प्रतिवाय करने में अवश्यता

प्रयदा अनिच्छा के कारण नकास्पद हो गई है और ऐसे अणों को पूर्णगामी बंड (क) से (घ) में सम्मिलित नहीं किया गया है।"

[नं. 9029/का.सं. 142/29/91-टीपीएल(भाग)]  
प्रदिव्येश प्रमाण, निवेशक (टीपीएल-1)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 1992

## INCOME-TAX

S.O. 357(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Tenth Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall be deemed to come into force the 1st day of April, 1991.

2. In the Income-tax Rules, 1962,

after rule 6E, the following rule shall be inserted, namely :—

"6EA. The provisions of section 43D shall apply in the case of every public financial institution, scheduled bank, State financial corporation and State industrial investment corporation where its income by way of interest pertains to the following categories of bad and doubtful debts, namely :—

(a)(i) Non-viable or sticky advances, [i.e., where irregularities of the nature specified in sub-clause (ii) are noticed in the accounts of the borrowers for a period of six months and more and there are no minimum prospects of regularisation of accounts, or where the accounts or information in relation to such accounts reflect usual signs of sickness, such as,—

1. apparent stagnation in the business as a result of the slow or negligible turnover ;
2. frequent requests for over-drawing or issue of cheques without ensuring availability of funds in the account;
3. bills purchased or discounted remain overdue for 3 months and more or the recovery of such bills from the borrower poses difficulties ;
4. in the case of term-loans, instalments which are overdue for 6 months or more;
5. unexplained delays by the borrower in submission of quarterly or half-yearly operating statements or stock statements or balance sheets and other information required by the bank;
6. slow movement or stagnation of stocks observed during inspections ;
7. low or negligible level of activity observed during inspections or suspension or closure of the business;

- 8. persistent delay in compliance with vital requirements like execution of documents, producing additional security when required or non-compliance with such requirements;
- 9. diversion of funds to sister units or acquiring capital assets not relevant to the business or large personal withdrawals by the borrowers;
- 10. international non-adherence to project schedules leading to substantial cost escalations and requirement of additional term-finance.
- 11. the pressure on the liquidity leading to non-payment of wages to workers or statutory dues or rents of office and factory premises;
- 12. the current liabilities exceeding current assets;
- 13. any grave irregularities observed by the auditors of the borrowers which remain to be rectified;
- 14. basic weakness revealed by the financial statements of the unit, for example, continued cash loss beyond one year.

(ii) The irregularities referred to in sub-clause (i) in the accounts of the borrowers are,—

- 1. where the accounts are over-drawn beyond the drawing power or the sanctioned limit, for a temporary period;
- 2. instalments in respect of term loan are overdue for less than 6 months or import bills under letters of credit or instalments under deferred payment carried are over due for less than 3 months;
- 3. bills not exceeding 10 per cent to 15 per cent of the total outstanding in the bills purchased or discounted account of the borrower are overdue for payment for a period of less than 3 months and refund in respect of unpaid bills is not forthcoming immediately.]

(b) Advances recalled, i.e., where the repayment is highly doubtful and revival of the unit is not considered worthwhile and a decision has been taken to recall the advances.

(c) suit-filed accounts, i.e., where legal action or recovery proceedings have been initiated and suits are pending for recovery of advances.

(d) decreed debts, i.e., where suits have been filed and decree obtained and such decree is pending for execution.

(e) Debts recoverability whereof has become doubtful on account of shortfalls in value of security, difficulty in enforcing and realising the securities, or inability or unwillingness of the borrower to repay the banks dues—partly or wholly and such debts have not been included in preceding clauses (a) to (d)."

[No. 9029/F. No. 142/29/91-TPL (Part)]  
AKHILESH PRASAD, Director (TPL-I)

